उत्तराखण्ड शासन

Budget

Suggestions

Year

2025-26

✎ *परम आदरणीय महोदय,*

जैसा कि सभी को विदित है कि उत्तराखंड में यात्रा सीजन के दौरान भारी मात्रा में पर्यटक आते हैं तथा स्थानीय लोगों का भी साल भर आवागमन रहता है इस आवागमन में महिलाओं को, शौचालय की व्यवस्था न होने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है पर्यटकों को खुले में मूत्र विसर्जन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है इसी प्रकार स्थानीय महिलाओं को भी कई बार दिक्कतें होती हैं

मेरा आग्रह है कि सड़क मार्ग पर हर 5 किलोमीटर पर विशेष रूप से महिलाओं के लिए शौचालय बनाने का कार्य किया जाए, जिसके लिए बजट में अलग सा प्रावधान हो.

सुशील कुमार राज

नई टिहरी

✎ *पड़े लिखे डिग्रीधारी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए*

और युवाओं को नौकरी दी जानी चाहिए

हर घर मैं एक युवा को योग्यता के अनुसार सरकारी सेवा मैं शामिल होने का मौका दिया जाना चाहिए इसके लिए आप विद्वानों की सहायता से सहमति लें और सेवानिवृत्ति की आयु60 से 55 भी की जा सकती हैं जिससे सभी को नौकरी के समान अवसर मिल सकें।

✎ *बजट 2025-26 में हमारा सुझाव-*

1. युवाओं के लिए कौशल विकास एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए बजट होना चाहिए

2. पर्वतीय ग्रामीण विकास के लिए बजट होना चाहिए जिससे पलायन रुकेगा,हमारे पहाड़ में रोजगार की कमी से ही लोग पलायन कर रहे हैं

3. पर्यटन का विकास के लिए बजट होना चाहिए हमारे पहाड़ों में

आगे भी हम समय के साथ साथ अपने सुझाव रखेंगे धन्यवाद!

✎ *माननीय मुख्यमंत्री जी सादर प्रणाम....*

माननीय मुख्यमंत्री जी मैं त्रिलोचन प्रसाद

माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन है कि महोदय मैं अन्य पिछड़ा वर्ग से आता हूँ लेकिन पिछले साल से अधिकारियों की लापरवाही से हमारे ओबीसी प्रमाण पत्र बन ही नहीं रहे हैं जिससे हमको स्कूल और कॉलेज और सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है अतः आपसे निवेदन है कि इस पर कार्रवाई करने का कष्ट कीजियेगा.....

- *माननीय वित्त मंत्री उत्तराखंड सरकार से मेरा सुझाव निवेदन है कि १---उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि के रकबे को बनाया रखने हेतु काश्तकारों को प्रोत्साहन दिया जाय।*

२---जो खेती नहीं कर रहे हैं उन्हें रासन देना बंद किया जाय।

३--जो खेती कर रहे हैं उन्हें बीज मशीनरी खाद हेतु सब्सिडी दी जाय।

४--जो खेती नहीं कर रहे हैं उन्हें कोई सब्सिडी न दी जाए।

५--जो खेती कर रहे हैं उनके ऋण माफ किया जाय।

६--जो खेती नहीं कर रहे हैं उनके ऋण माफ न किया जाए।

७--खेती किसानी को बंदर भालू हिरन सौल काकड़ सूउर लंगूर रात दिन बर्बाद करने में लगे हैं। इनके बचाव के लिए कृषि मंत्रालय ने ठोस गंभीर अति संवेदनशील क़दम उठाए जाऐ।

८--पहाड़ों पर अब बारीस पानी हिमपात कम हो गया है बल्कि न के बराबर हो गया है।इस हेतु फसल पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ रहा है। सरकारी अमला ने बहुत जोरदार प्रयास करना होगी।

९--माननीय महोदय पहाड़ की संपुर्ण कृषि भूमि को चकबंदी का समय आ गई है।

१०--संपूर्ण उत्तराखंड में बहुत अधिक जमीन जहां जनता पैसा देकर बैठ गई है।वो जमीन उसके नाम पर कर दिया जाय।

चौकोड़ी पिथौरागढ़ नैनीताल वीर भट्टी जैसे जहां मालदार ने जनता को ज़मीन पैसा लेकर दे दी है वो जमीन के पक्के कागज एवम् रजिस्ट्री जनता के नाम अवश्य ही होनी चाहिए।

महोदय सुझाव तो अनगिनत हैं। लेकिन हात जोड़ कर विनती है।इन सुझावों को अमली जामा अवश्य ही पहनाएं।

हीरा सिंह गैड़ा

चौकोड़ी

2025 26 हेतु तैयार किया जा रहे बजट मैं सुझाव प्रेषित किए जाने के संबंधमें।

१. निर्माण कार्यों हेतु जारी किए जा रहे बजट में निर्माण कार्यों हेतु धनराशि का आवंटन सुनिश्चित स HBमय पर किए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए अर्थात समय बजट कार्यों हेतु बजट की उपलब्धता समय कराई जाए

2. करदाई संस्था कार्य दी संस्था को बजट आवंटन के साथ ही कार्य को निश्चित समय अंतर्गत पूर्ण करने की तारीख बजट जारी करने के शासनादेश में ही उल्लेखित की जाए।

3. कार्यदाई संस्था यदि कार्य को समयबद्ध संपन्न नहीं कर पाती है तो वित्तीय कटौती के साथ-साथ दंड की भी व्यवस्था की जाए। करदाई संस्था के साथ-साथ मॉनिटरिंग करने वाले अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय की जाए।

4. ग्रामीण इलाकों में खासकर बॉर्डर से जुड़े गांवों में पलायन न करने वाले लोग जो के जॉकी अपने मूल गांव में रहकर ही कृषि आधारित व्यवस्थाओं अथवा अन्य कार्यों से जीवन निर्वाह कर रहे हैं हेतु एक निश्चित प्रोत्साहन प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था बजट में की जाए इससे पलायन को रोकने में निश्चित ही सफलता मिलेगी

5. बॉर्डर के गांव में रह रहे युवाओं हेतु अग्नि वीर जैसी योजनाओं में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए तथा बाद में उन्हें सेवा से जोड़कर ही बॉर्डर के गांव में ही तैनात किया जाए अर्थात जिम्मेदारी दी जाए इसके बदले में उन्हें उचित मानदेय सेवा नियमों के तहत दिया जाए इससे एक तो बॉर्डर के गांव

की सुरक्षा से देश की सुरक्षा बढ़ेगी वह बॉर्डर से पलायन की समस्या दूर होगी इस हेतु भारत सरकार से भी बजट की मांग की जा सकती है क्योंकि यह देश की सुरक्षा का विषय है।

6. बजट में आवश्यक रूप से शिक्षा पर प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक बढ़ोतरी करने की आवश्यकता है। खासकर निर्माण कार्यों हेतु अथवा अर्थात विद्यालयों के भवन एवं फर्नीचर वह प्रयोगशालाएं वह प्रयोगशाला उपकरणों पर बजट की व्यवस्था में बढ़ोतरी की आवश्यकता है।

7. तकनीकी एवं मेडिकल शिक्षा में रोजगारपरक पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने पर जोर दिया जाना चाहिए।

8. चिकित्सा के क्षेत्र में कम से कम पंचायत स्तर पर एक फार्मासिस्ट की नियुक्ति हेतु बजट की व्यवस्था की जानी चाहिए एवं इस फार्मासिस्ट के निर्देशन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना का प्रावधान हेतु बजट में व्यवस्था की जानी चाहिए।

9. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कम से कम प्रत्येक जिले में भौगोलिक स्थितियों के मध्य नजर एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए जो की जिले के महाविद्यालयों की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित कर सके तथा वर्तमान परिपेक्ष में उच्च शिक्षा की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके।

10. उत्तराखंड की भौगोलिक स्थितियों के मध्य नजर आपदा में तुरंत सहायता पहुंचाने हेतु कम से कम ब्लॉक स्तर पर एक आपदा प्रबंधन केंद्र की स्थापना हेतु कवायद प्रारंभ की जाए। वर्तमान में ब्लॉक

कार्यालय अर्थात विकासखंड कार्यालय में आपदा प्रबंधन केंद्र हेतु व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने किए आदेश तत्काल रूप से दिए जा सकते हैं जहां पर आपदा ग्रस्त क्षेत्र एवं आपदा संभावित क्षेत्रों की संभावित सूची तैयार कर आपदा से निपटाने हेतु आवश्यक तैयारियां की जानी चाहिए।

11. खेलों में प्रोत्साहन हेतु प्रत्येक विद्यालय स्तर पर खेल बजट की व्यवस्था एवं उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थियों को उच्च प्रशिक्षण हेतु बजट की व्यवस्था होनी चाहिए। स्वस्थ समाज हेतु स्वस्थ मस्तिष्क की आवश्यकता होगी और स्वस्थ मस्तिष्क हेतु शारीरिक स्वस्थता आवश्यक है।

12. गांवों को सेल्फ सस्टेन बनाने हेतु पंचायत स्तर पर व्यवस्थाएं विकसित करने हेतु कार्य योजनाएं तैयार की जाए प्रत्येक गांव को किस प्रकार से सुविधा संपन्न बनाया जा सके इस हेतु जिला स्तर पर जिला अधिकारी के तत्वाधान में पंचायत स्तर की कमेटी गठित कर प्रत्येक गांव की भौगोलिक परिस्थितियों का अध्ययन कर कार्ययोजनाएं तैयार की जाए। इसमें यदि इसमें यदि एक्सपट्र्स की जरूरत हो तो इस हेतु आवश्यक बजट जिला अधिकारी कोष से उपलब्ध कराया जाए। कार्य योजना तैयार करने से तात्पर्य उसे गांव की स्थिति को देखते हुए वहां किस प्रकार की खेती की जा सकती है वहां किस प्रकार का पशुपालन किया जा सकता है वहां किस प्रकार के उद्यान विकसित किया जा सकते हैं वहां किस प्रकार के उद्योग की संभावना हो सकती है या वहां किस प्रकार के लघु उद्योग सस्टेन कर सकते हैं जिससे उसे गांव की आर्थिक की बहुत सामाजिक स्थिति में आमूल चूल परिवर्तन परिलक्षित हो सके।13. उत्तराखंड क्षेत्र से प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाने वाले विद्यार्थियों को उनके क्षेत्र

में उच्च प्रशिक्षण की व्यवस्था हेतु बजट की व्यवस्था होनी चाहिए राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में मेरिट में आने वाले विद्यार्थियों को यदि उनकी आर्थिक स्थिति समाचीन ना हो तो आर्थिक मदद हेतु जैसे कि उनके शिक्षण शुल्क हेतु बजट की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सके इस हेतु आवश्यक रूप से उच्च शिक्षा के केंद्रों को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए।

14. रोड एक्सीडेंट, जंगली जानवरों के हमले से घायल अथवा मृत व्यक्तियों जंगली जानवरों से कृषि को होने वाली हानि आदिआदि आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को संबंधित विभागों से मुआवजा राशि दिलाने के प्रावधान वह इस हेतु बजट की व्यवस्था हेतु विभागों को कार्रवाई करने के साथ-साथ विभागों की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

दिनेश चंद्र पुरोहित,
दून विश्वविद्यालय देहरादून

नाम – कुमार मंगलम सेमवाल

संपर्क – 8938804746

सुझाव – विद्यालयी शिक्षा एवं उच्च शिक्षा में योग शिक्षकों के लिए आवश्यक बजट पारित किया जाए।

ताकि छात्रों को इसका लाभ मिल सके।

अध्यक्ष (राष्ट्रीय योग शिक्षक महासंघ)

सेवा में,

मा० श्री पुष्कर सिंह धामी जी
मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखंड

विषय:— बजट 2025-26 हेतु सुझाव/आग्रह

महोदय,

केन्द्र और राज्य सरकार देश की पारम्परिक मान्यताओं को संरक्षण देने का काम कर रही हैं। लेकिन देश के असली पारम्परिक वैद्यों को आप हतोत्साहित करने करने का काम कर रहे हैं। भारतीय चिकित्सा परिषद् के वर्तमान अध्यक्ष श्री जे. एन. नौटियाल नहीं चाहते कि असली पारम्परिक वैद्यों को प्रोत्साहन मिले, जिस तरह से एलोपैथी के डाक्टर आयुर्वेदिक डाक्टरों की उपेक्षा करते हैं। उसी तरह से आयुर्वेदिक डाक्टर हम पारम्परिक वैद्यों को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। आप डा. नौटियाल के अनुसार चलते हैं। हम लोग ऐसे रोगों का इलाज करते हैं जिनको एलोपैथी और आयुर्वेदिक डाक्टर असाध्य बता देते हैं।

अतः आप से निवेदन है कि हम लोगों को प्रदेश, देश व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहन देने की कृपा कीजिएगा

भवदीय [signature]
वैद्य सुरेश चन्द्र डबराल
माइग्रेन व दर्द रोग विशेषज्ञ
फोन 9719721861, उत्तराखंड

✎ *किसन सिंह बिष्ट*

9997099765

प्लीज विद्यालयी शिक्षा माध्यमिक में और उच्च शिक्षा में योग के लिए अनिवार्य बजट की व्यवस्था की जाए ताकि समस्त विद्यार्थी और स्कूल योग से अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें

✎ ***uttarakhand बजट के लिए मेरा सुझाव है की prd जवानो के लिए पक्की व्यवस्था हो।खान पान भत्ते अलआऊंसैस सब पर्याप्त मात्रा में हो। तनख्वाह अच्छी हो। ड्यूटी का शेड्यूल सही हो। अनुशासित रहे इसके लिए पक्की व्यवस्था हो।***

Prd महिलाऔं की अलग-अलग बटालियन हो। इनके लिए भी सेम व्यवस्था हौ

आने वाले समय में होमगार्ड के जवान उत्तराखंड की रीढ़ की हड्डी साबित होंगे

जय कुमाऊं जय उत्तराखंड

हीरा सिंह गैड़ा

चौकौडी कोटना नगर

Budget 2025-2026 Suggestions

Add label

mohan bhatiya 1:32 pm

to budget-uk

We give below a couple of Suggestions in respect of the above
1- We being a state with huge tourism potential, we need to immediately go for public private partnership in running several idle and unprofessionally run tourist homes which are situated in prime locations.It will definitely help in enhancing state government 's income and will add up to substantial employment.
2- Also, we need to handle religious tourism more professionally by providing better transportation and accomodation facilities.Here , local youth could be encouraged to be more participative by providing them necessary guidance,training and financial support.
3- HOWEVER, TO BECOME NUMERO UNO STATE IN THE COUNTRY, IS TO STOP MASSIVE ALL OUT CORRUPTION PREVALENT HERE ,WHICH IS ORIGINATED FROM HELPING OUTSIDERS TO ESTABLISH THEIR BUSINESS IN UTTRAKHAND AND LOCALS ARE REAL SUFFERERS

Regards,

- उत्तराखंड में शहरों में हो रहे अनियंत्रित विकास जैसे कि अनियंत्रित प्लाटिंग कृषि भूमि को आवासीय भूमि में तब्दील कर अथवा बिना तब्दील किये ही उस पर प्लाटिंग के माध्यम से आवासीय भवनों का निर्माण किया जा रहा है जो कि बिना किसी प्लानिंग के अर्थात बिजली पानी शिविर लाइन अथवा सड़क की व्यवस्था के बिना कॉलोनाइजर्स द्वारा अपने लाभ के लिए कार्य किया जा रहा है ।

आवश्यकता इस बात की है कि राज्य में सभी शहरों में या भविष्य में शहरों की श्रेणी में आने वाले कस्बों में टाउन प्लानिंग के लिए सर्वप्रथम कृषि भूमि व आवासीय भूमि का चयन करने हेतु बजट का निर्धारण किया जाए तथा जहां तक संभव हो निर्माण कार्य केवल बंजर भूमि अथवा ऐसी चिह्नित भूमि जिस पर कृषि ना की जा सके पर ही केंद्रित हो यदि आवश्यक हो तो कृषि भूमि पर आने वाले कुछ वर्षों तक आवासीय प्रयोग के लिए बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। किसी भी भूमि पर प्लाटिंग के लिए आवश्यक दिशा निर्देश तैयार कर उन्ही दिशा निर्देशों के अनुसार निर्माण कार्यों के लिए इजाजत दी जाए। प्रत्येक प्लाटिंग में सड़कों की चौड़ाई वह बिजली पानी सिविर लाइन व संचार लाइन हेतु व्यवस्था होने पर ही फ्लर्टिंग की इजाजत दी जाए।

उपरोक्त कार्यों के चिह्नीकरण हेतु प्रत्येक जिला अधिकारी के माध्यम से आने वाले समय के लिए आवश्यक रूप से बजट की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे शहरों में हो रहे अनियंत्रित निर्माण को नियंत्रित किया जा सके।

✎ ***I want to suggest a few points that you can consider and provide budget for the following projects.***

1) Construction of the State Museum of Uttrakhand.

2) Construction of the International Convention Center and Wellness City at Rishikesh (land previously held by IDPL).

3) Purchase of New Buses.

4) Construction of helipad at every block to facilitate Heli ambulance service.

5) Construction of Singtali bridge.

✎ *परम् सम्मानित मेरे गाँव के समस्त गाँव वासियों को मकर सक्रांति की शुभ कामनाएं मेरी भगवान गणजेश्वर महादेव अपने त्रिदेवों ऋषि जाख माता चंड़िका मलका देवी नंदा देवी मुंडा देवता और भूमि*

के रछक बिस्कम देव को प्रणाम करते हुए बिनती है भविष्य में मेरे इन तीनों गावों में कुछ ऐसी अप्रिय घटना न जिससे हमें भारी दुखी और सौकाकुल न होना पड़े क्योंकि ऐसी घटनाएं न पीड़ित परिवार को ही दुखी करती हैं बल्कि इससे सारी जनता दुखी हो जाती है हमें अपना ही सुख और अपनी ही कामयाबी की कल्पना नहीं करनी चाहिए हमें अपने आस पास अगल बगल अपने सारे ग्राम वासियों की सुख और कामयाबी की प्रार्थना उस परम् पिता परमेश्वर से करनी चाहिए .

मेरा आप सभी बुजुर्ग माताओं से बहिनों नव युवक नौजवानों से बुजुर्गो से वच्चों से अपने दोनों हाथ जोड़कर सप्रेम बिनती है हम सब मिलकर अपने गाँव को समाज की दृस्टि से शासन प्रशासन की दृस्टि से और मानवता की दृस्टि से और विकास की दृस्टि से एक नई दिशा दें.

मेरा अनुरोध है मैं एक वन पंचायत सरपंच हूँ और मैं वनों की ही बात करूंगा लेकिन ऐसा नहीं है मैं पहले गाँव में रहता हूँ क्योंकि गाँव भी जंगलों के बीच के भू भाग पर ही बसा है और उस गाँव के भले और हित के बारे में भी सोचने और कुछ करने का मेरा पहला कर्तब्य है यह मेरा ही नहीं बल्कि हम सब का है और आती है बात जंगल की अगर हमारे आसपास जगल है तो उसकी देखभाल भी हमें ही करनी है.

अगर जंगल में पेड़ पौधे रहेंगे तभी वह जंगल कहलाएगा अगर जंगल रहेगा तो हमें जंगल से हवा पानी जलावन के लिए लकड़ी जानवरों को खाने के लिए चारा घास बिछावन के लिए पत्ती और पीने के लिए जल यह सब जंगल से मिलेगा.

सरकार मुझ जैसे सरपंचों उत्तराखण्ड के सरपंचों को जंगल को कैसे बचाया जाय इसका ज्ञान प्राप्त करने व सीखने के लिए अल्मोड़ा जिले के (शीतला खेत) भेज रही है जहाँ मैं भी दशोली के सरपंचों का अध्यक्ष होने के नाते वद्रीनाथ वन प्रभाग के माध्यम से गुम कर आया हूँ मैंने भी देखा वहां की30 ग्राम पंचायत की महिला मंगल दल और युवक मंगल दल और वहां की जनता ने कैसे अपने जंगलों को वचा के रखा किसी गाँव की सुंदरता उस गाँव में रहने वालों के सुन्दर चेहरों से नहीं लगाई जाती बल्कि उस गाँव के चारों तरफ में वने जंगलों पेड़ पौधों से बनती है यही सच है

मेरी आप सभी से बिनती है कि आप अपने जंगलों पेड़ पौधों को बचाने और इसे आग से बचाने में मेरी मदद करें हम भी अपनी वन पंचायत कुजों मैकोट भी शीतला खेत की तरह बचाएं और बाहर गाँवों से लोग भी हमारे गाँव आएं देखने के लिए कैसे इन्होने अपने जंगलों कोवचा के रखा है

वनाग्नि जैसी बिनासकारी आपदा को न आने दे और जंगलों हरे पेड़ पौधों को न काटें

क्योंकि जंगल बचे रहेंगे तो हमारा जीवन बचेगा अगर जंगल नहीं तो हमारा जीवन ब्यर्थ है

अंत में आप सभी से मेरी ??जोड़कर बिनती है आप मेरा सहयोग करें और अपने गाँव को एक आदर्श गाँव बना सके ??

धन्यवाद

श्री किशन सिंह बिष्ट

वन पंचायत सरपंच कुर्जों मैकोट

दशोली चमोली

उत्तराखंड

सेवा में,

श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी,
मा0 मुख्यमंत्री महोदय,
उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

विषय - बजट निर्माण पृक्रिया 2025-26 में प्रार्थी के द्वारा प्रेषित किए जा रहे निम्न सुझावों को सम्मिलित कराए जाने के संबन्ध में अति आवश्यक प्रार्थना ।

माननीय महोदय,

नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं सहित प्रार्थी के द्वारा आगामी बजट निर्माण पृक्रिया 2025-26 में देव भूमि उत्तराखण्ड की देव तुल्य जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप निम्न महत्वपूर्ण सुझावों को प्रेषित करते हुए यह प्रार्थना है कि महोदय निम्नलिखित किसान हितैसी सुझावों को शासन स्तर पर अनिवार्य रूप से बजट निर्माण पृक्रिया में सम्मिलित कराने में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान कीजिएगा।

सुझाव नं0-1

देव भूमि कामधेनु (बद्री गाय) संरक्षण योजना:- देव भूमि उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में हमारी पूज्य आराधया कामधेनु गौमाता (बद्री गाय) का पिछले कुछ वर्षो से घोर अपमान होता आ रहा है, छोटा कद होने तथा कम दूध देने के वजह से लोग बद्री गाय पालने के बजाय विदेशी नस्ल की गायों को जयादा महत्व देते आ रहे हैं, जबकि देव भूमि उत्तराखण्ड के अंतर्गत हर घर में बद्री गाय का पालन किया जाना धार्मिक दृष्टि से भी अत्यन्त आवश्यक है।

अत:बद्री गाय के संरक्षण हेतु शासन द्वारा एक विषेश योजना बना कर इसे आगामी बजट निर्माण में प्रथम स्थान दिलाए जाने की कृपा कीजिएगा।

सुझाव नं0-2

देव भूमि जडी़-बूटी संरक्षण योजना:- देव भूमि उत्तराखण्ड (मध्य हिमालयी क्षेत्र) में प्राकृतिक जीवन दायिनी जडी़-बूटियों का अपार भंडार है, और यहाँ के पर्वतीय किसानों के पास कृषि भूमि का क्षेत्रफल निरंतर कम होता जा रहा है ऐसी परिस्थिति में यहाँ के किसानों को सगंध पौधों की खेती, व प्राकृतिक जीवन दायिनी जडी़-बूटियों की खेती कराऐ जाने हेतु पॉलीहाउस की तर्ज पर अनुदान आधारित एक विशेष योजना बना कर इसे भी देव भूमि के किसानों के हित में आगामी _बजट निर्माण में अनिवार्य रूप से सम्मिलित कराऐ जाने की कृपा कीजिएगा।

स-धन्यवाद।

दिनांक:- 18/01/2025

शुभाकाँक्षी

नारायण सिंह कुल्याल
वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता
ग्राम- जंगलियागाँव
वि0ख0- भीमताल, जिला- नैनीताल, उत्तराखण्ड।
मो0- 8126669574

अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन W.A. No 9520820623

विषय :- जनता का बजट जनता के द्वारा 2025-26

Sir
1:- I am a veteran having 80 years of age, very happy you are asking advices from the people of 13 District and 95 Blocks of U.K. Accordingly my advice are enumerated below for the budget for financial year 2025-26 :- जनता में चार वर्ग हैं। उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग एवं अंन्तोदय शायद कोई भी गाँव ऐसा नही होगा, जहाँ जंगली जानवरों का प्रकोप नही होगा, जिस कारण हर व्यक्ति बाजार पर निर्भर है, रोटी, कपड़ा और मकान यह प्रथम आवश्यकता है। बाजार में पदार्थों की कीमत घटती बढ़ती जाती है, जैसे सोना, चाँदी, लोहा, पैट्रोल, डीजल, सीमेन्ट आदि, मनुष्य की आवश्यकता अनन्त हैं, जिसके पास आज 99 रु० है, कल उसे 100 रु० बनाने की कोशिश करता है, संतोष किसी को नही है, सरकारी तंत्र में सभी नही कुछ ऐसे हैं जो ऑफिस में या कार्य स्थल में देरी से जाएँ और जल्दी घर आ जाएँ कैसा ही बजट बनाओगे सरकार को ही नाम रखेगा, मैं क्या कर रहा हूँ नही सोचता है, कि राष्ट्र सेवा प्रथम है। फ्री राशन से और भी आलसी हो रहे हैं, फ्री राशन नया-नया फैशन जगह-जगह दारू की दुकान और बेरोजगारी से देवभूमि की देवतुल्य जनता में सभी नही कुछ ऐसे लोग हो गये हैं, वही याद आती है "दिन का सूर्य अस्त उ० ख० का आदमी मस्त" मुझे जगह-जगह भाषण देना का मौका मिलता है, मेरी सर्वप्रथम राय यही होती है, सबसे पहले अपने को देखो कि मैं कैसा हूँ क्या कर रहा हूँ "Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow" and be happy because contentment is greatest happiness. "An honest work of the man is the noblest work for god"

2:- आप बजट बनाने में व्यस्त है, जैसा भी बनाओगे वही अच्छा होगा, क्योंकि आप सबसे राय ले रहे हैं इसका मतलब मेरी तरफ से "your idea is exemplary and appreciable: with my best wishes for the subject matters.

Date:- 23 january 2025
Mob No- 9412915137
whats App No- 9457269568
Place:- vill&Po- Kanda [illegible]
[illegible] Teh. Kandu Dist- Bageshwar-U.K.
PIN- 263640

with warm regards
your faithfully
[signature]
(Puran chandra Lohani)

- ***Mera Yahan sujhav Hai Sar ji ki BPL Ration card Walon ke ration card Nahin Bane hain aur jo acche Hain Naukari Wale Hain unke ration card Bane Hain kripya ismein Santosh sanshodhan Karen Hamara ration card Nahin Banaya Ham majdur aadami Hain***

✎ *TO RAISE REVRNE OF UTTRKHAND GOVT*

GOVT SHOULD IMPOSE A HONORABLE PROFESDIONAL TAX ON EVERY CITIZEN WHO IS EARNING FROM ANY SOURCE

Up to 5 lakh 100 per annum

5 to 10 300 per snnum

10 lakh to 25 lakh 1000

25 lakh and above 5000

EVERY CITIZEN WHO PAY THIS TAX WILL CALLED A HONOURABLE TAX PAYER AND A CARD WILL BE ISSUED TO HIM AS ID TO TAKE ANY LICENSE CODE NO LOAN ETC

SHARVAN KUMAR AGGARWAL GARG SIR

Retired office superintendent from SURVEY OF INDIA

83/2PURVI PATEL NAGAR DEHRADUN

PH 0135 2720942

Mob 7417925472

✎ नमस्कार सर। यू सी सी लागू करने के लिए धन्यवाद।

सर बजट ऐसा हो जो सभी लोगों को एक समान रूप से प्रभावित कर सके । विशेष रूप से ग्रामीण एरिया में ज्यादा काम हो क्योंकि पहाड़ी इलाकों में काम होने से पलायन रुकेगा और प्रतिब्यक्ति आय बड़ेगी।जो भी योजना बने उसकी गुणवत्ता ठीक होनी चाहिए ।

मोहन खोलिया
गौजाजाली हल्द्वानी
जिला नैनीताल
उत्तराखंड

✎ *मान्यवर मुख्यमंत्री जी नमस्कार*

उत्तराखंड के बजट में सभी जनता के स्वस्थ्य को ध्यान में रखते हुए मेरा विचार

आप के द्वारा चलाई जा रही योजना आयुष्मान जो सभी लोग को लाभकारी योजना के तहत से लागू है इस में कोई सुधार की आवश्यकता है

प्रथम गरीबों के लिए होनी चाहिए

दूतिय जैसे फसलों का इंस्योरेंस होता है उस तरह से बाकी जनता का हो

तीसरा अभी भी कुछ specialised branch इसमें सामिल नहीं है उन्होंने भी इस में सामील किया जाना चाहिए जैसे दर्द रोग विशेषज्ञ

दर्द रोग विशेषज्ञ कीसी भी दर्द का इलाज दवाइयां;नर्व बलोक एवं radio frequency जौसे तरीके से करते हैं जो कम खर्च में होता है

इंस्योरेंस में परामर्श शुल्क मुफ्त हो तो अच्छा है

मेंरा नाम डॉक्टर राम सुभग सिंह
फोन नं 9897902780

- *मेरा नाम अनुराग शर्मा है मैं हरिद्वार जिले के ग्राम बहादुरपुर जट रहने वाला हूं। बजट के बारे में मेरा सुझाव यह है कि हम सब किसान लोगों के खेतों के रास्ते कच्चे हैं। बजट में इन रास्तों को पक्के करने का प्रावधान भी होना चाहिए और इसके लिए अलग से राशि होनी चाहिए*

✎ *मैं आगामी बजट के बारे मैं अपने निम्न २ सुझाव देना छाता हूँ ।*

१-सभी ज़िलो मैं सेना भर्ती ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट की स्थापना हो ताकि जो नवजवान आर्म्ड सर्विसेज मैं जाना चाहे उन्हें उचित ट्रेनिंग मिल सके ।

२-४५ साल से कम उम्र के बेरोजगार युवाओ को पाँच लाख रुपये ग्राम प्रधान की संस्तुति पर ४% रेट ऑफ़ इंटरेस्ट पर मुर्गी पालन, दुग्ध विकाश, आर्गेनिक शब्जी उत्पादन हेतु सहायता मिले

सी एस पांडेय

9915806751

सेवा मे

श्रीमान अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन

विषय:- बजट 2025-26 निर्माण प्रक्रिया में जनभागीदारी सुनिश्चित किये जाने हेतु।

महोदय, जैसा कि विदित है कि 2024-2025 बजट का कार्यक्रम गतिमान अवस्था में है। उत्तराखंड जैसे पर्वतीय प्रदेश मे रोजगार के साधन कम हैं। प्रति व्यक्ति आय भी कम है। कुछ लोग अपना काम भेड़ बकरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, मौन पालन, या मनरेगा मे कार्य करके अपनी आजीविका चलाते है। पहाड़ों में तो पलायन लगातार बढ़ रहा है, जोकि चिंता का विषय है। हां शराब जैसी वस्तुओं पर, स्टांप शुल्क, जमीन का सर्किल रेट एवं साहसिक खेल, इत्यादि पर कर बढ़ाया जा सकता है। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था, अभी भी कई ग्रामों में स्वच्छता हेतु ग्राम सभा में राज्य सरकार द्वारा या केन्द्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को बजट दिया जाय। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त वित्त की व्यवस्था करना भी राज्य सरकार का प्रमुख कर्तव्य है।

धन्यवाद

दिनांक
24/1/2025

(हस्ताक्षर)
राजेश पंत
देवप्रयाग उत्तराखंड

✍ *वेरी गुड इवनिंग सर*

राज्य में अलग-अलग तरह की समस्याएं हैं और टेक्नोलॉजी/इनोवेशन के इस दौर में बड़ी-बड़ी समस्याओं के भी आसान समाधान उपलब्ध है

राज्य में कार्य करने का बहुत स्कोप है, कई क्षेत्रों में अभूतपूर्व कार्य किए जा सकते हैं और टेक्नोलॉजी के माध्यम से सरलीकरण किया जा सकता है

सिर्फ जरूरत है उस कार्य को समझकर उसे अंजाम देने वाले लोगों की।

महोदय राज्य में जितने भी डिपार्टमेंट से मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि सभी डिपार्टमेंट में एक आर &डी (R&D) विंग बनाया जाए तथा उस आर&डी विंग में जो भी इंटरेस्टेड एवं योग्य व्यक्ति राज्य हित में कार्य करने हेतु पैशनेट हो उसे संविदा के आधार पर रखकर कार्य करवाया जाए

जिसका कार्य केवल विभागीय Innovation और गूढ अनुसंधान पर केंद्रित हो

माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल अथवा महत्तवपूर्ण बड़े विभागों में R&D विंग बनाया जाना चाहिए और यह युवा/ विशेषज्ञ माननीय मुख्यमंत्री महोदय/ मंत्रियों के अंतर्गत आने वाले सभी विभागों की मॉनिटरिंग करेंगे तथा अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे।

इन युवाओं का कार्य ब्रेनस्टॉर्मिंग का रहेगा जिसमें यह विकट समस्याओं का कैसे आसानी से सुलझाए जा सकता है इस हेतु कार्य करेंगे युवाओं को देशभर से आमंत्रित किया जा सकता है

जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों आई आई एम ,आईआईटी, TISS, जेएनयू या कोई अन्य संस्थान या कोई पैशनेट व्यक्ति जो राज्य हित में कार्य करना चाहता हो और उसको रूटीन काम में ना उलझा कर विभागीय कार्यों और इनोवेटिव सोलूशंस पर कार्य करने हेतु एक प्लेटफार्म दिए जाने की आवश्यकता है।

वह युवा राज्य/विभाग में हो रही सभी गतिविधियों पर नजर रखेगा और राज्य हित में क्या बेहतर तरीके से कार्य किया जा सकता है इस हेतु कार्य करेगा

महोदय पूर्व में मुख्यमंत्री युवा पेशेवर नीति को लाया गया था इसके माध्यम से ऐसे ही युवाओं को कार्य करने का मौका दिया गया था किंतु प्रशासनिक ढील के कारण योजना समाप्त कर दी गई

अतः आपसे निवेदन है कि कुछ ऐसी ही स्कीम पुनः लाई जाए जिसमें युवा पेशेवरों जोकि पहाड़ हित पर कार्य करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट के तौर पर लाया जाए और कार्य करवाए जाए।

कई विषयों पर मंत्रियों, अधिकारियों की व्यस्तता के कारण उन्हें हर चीज में बारीकी से ध्यान देने का समय नहीं हो पाता होगा किंतु सही सलाहकार होने से जो विषय विशेषज्ञ हो तथा सटीक जानकारी तथा उसके सुझाव/सलूशन दे सके, ऐसे लोगों को सिस्टम के भीतर लाए जाने की भी जरूरत है।

अत्यधिक लोगों की शिक्षा और कार्य में एकरूपता नहीं है , इसलिए राज्य की मूलभूत समस्याएं उनके समाधान मैं कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है

साथ ही को नई तकनीक आधारित विश्व में जो इनोवेटिव सलूशन हो रहे हैं।

अतः हर विभाग में अगर एक्सपर्ट बुलाए जाए जिनके पास संबंधित विषय का अनुभव हो और अपने कार्य को जिन्होंने प्रूफ किया हो ऐसे लोगों को सिस्टम में लाए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि योजनाएं तो बहुत सारी है और बहुत वर्षों से योजनाएं पर योजनाएं आ रही हैं लेकिन धरातल में योजनाओं का स्वरूप दिखाई ना देने से राज्य को नुकसान ही हुआ है और जो कि राज्य छोटा सा है और यहां कार्य करना इतना मुश्किल नहीं है जितना अन्य बड़े राज्यों में

अतः बेहतर होगा कि प्रशिक्षित विषय विशेषज्ञ विशेषज्ञों को लाकर चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो स्वास्थ्य कृषि हो टेक्नोलॉजी हो या कोई अन्य क्षेत्र हो विषय विशेषज्ञ प्रूवन सलूशन उपलब्ध कराएंगे।

R&D विंग विभागीय आत्मनिर्भरता , Innovation, विभागीय ख़र्चे कम से कम करने , efficiency बढ़ाने, आमदनी बनाने, जनता से कनेक्शन बनाने और sustainability पर कार्य करें,

सादर धन्यवाद

रुड़की में एकमात्र नेहरू स्टेडियम की हालत बेहद खस्ता है

यहां पर पटाखा बाजार, राजनीतिक रैलियां, धार्मिक आयोजन सरीखे कार्यक्रम होते हैं

केवल खेल गतिविधियां नहीं होती

इस बार के बजट में स्टेडियम का कायाकल्प होना चाहिए।

- *प्रधान मंत्री जी के विजन खेलों को बड़ावा देने हेतु प्राथमिक स्तर से शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य विषय बनाकर लागू करने का हमारे उत्तराखंड राज्य को भी साकार करना चाहिए।*

  आने वाले बजट में शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बजट अलग से रखना चाहिए।

  जिससे कि आने वाले समय में हमारा राज्य खेलों में अग्रणी बने और राज्य सरकार के साथ ही पूरे राज्य का नाम देश भर में गूंजे।

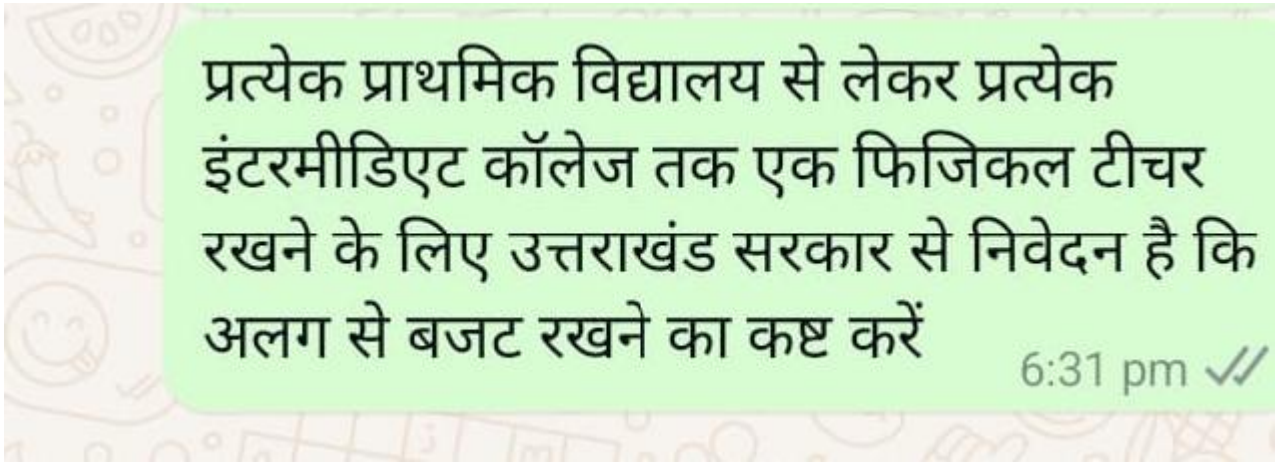
प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय से लेकर प्रत्येक इंटरमीडिएट कॉलेज तक एक फिजिकल टीचर रखने के लिए उत्तराखंड सरकार से निवेदन है कि अलग से बजट रखने का कष्ट करें
6:31 pm

- *उत्तराखंड सरकार को बजट में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में लगे योग अनुदेशकों को जो बहुत ही कम मानदेय मै कार्य कर रहे है। उसमें उन्हें अपनी दिनचर्या चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है सरकार को उनके लिए बजट का प्रावधान करना चाहिए,गोविंद सिंह मुनस्यारी पिथौरागढ़*

- *उत्तराखंड सरकार से अनुरोध है कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय से लेकर इंटरमीडिएट कॉलेज तक एक शारीरिक शिक्षा शिक्षक की नियुक्ति के लिए अलग से बजट निर्धारित किया जाए। इससे विद्यार्थियों को खेल-कूद के प्रति ध्यान आकर्षित हो। शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सर्वांगिक विकास का भरपूर अवसर मिल सकेगा।*

  अगर आज विद्यार्थियों की ओर देखा जाए तो विद्यार्थियों का समय सोशल मीडिया,फ्री फायर ,पबजी, टीवी आदि चीजों पर ही खोए रहते हैं। जिनसे विद्यार्थियों का मानसिक स्तर समाज से ध्यान भटक रहा है। इसलिए प्रत्येक विद्यालय में शारीरिक शिक्षक का होना अति आवश्यक है। ताकि विद्यार्थियों का ध्यान खेलकूद के प्रति ध्यान आकर्षित किया जा सके।

✎ *मैं आगामी बजट के बारे मैं अपने निम्न २ सुझाव देना छाता हूँ ।*

१-सभी ज़िलो मैं सेना भर्ती ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट की स्थापना हो ताकि जो नवजवान आर्म्ड सर्विसेज मैं जाना चाहे उन्हें उचित ट्रेनिंग मिल सके ।

२-४५ साल से कम उम्र के बेरोजगार युवाओ को पाँच लाख रुपये ग्राम प्रधान की संस्तुति पर ४% रेट ऑफ़ इंटरेस्ट पर मुर्गी पालन, दुग्ध विकाश, आर्गेनिक शब्जी उत्पादन हेतु सहायता मिले

सी एस पांडेय

9915806751

✏ *Petrol or diesel Ko GST Mai lay*

1 lakh salery waly jitny adhikari hai un ko do bhag mai kry 1 k badly 2 ko nokry milaigi 3 din Wark 3 din soshal wark kry

Nokry sai ritayar 50 sal Kary

Har pariwar Mai kam Sai kam 1 ko srkary nokry mily

Jis k ghr mai 1baity ho ush ki padhahi free ho jab Tak wo pdna chahiye

2 baity walo ki padhai ka adha kharch sarkar ly

Har thaika har permit mul niwashi ko mily

Phado ki jamino ka chakbandi kry khali jamino pr kishani kray yuwako ko kam dai

Tichar or Dr ko nokry ka adha hisha hil mai or adha phado mai kry

Khainy k liy bhuth Kuch hai galti k liye chama chata hu

9719724384...Narayan kshetri

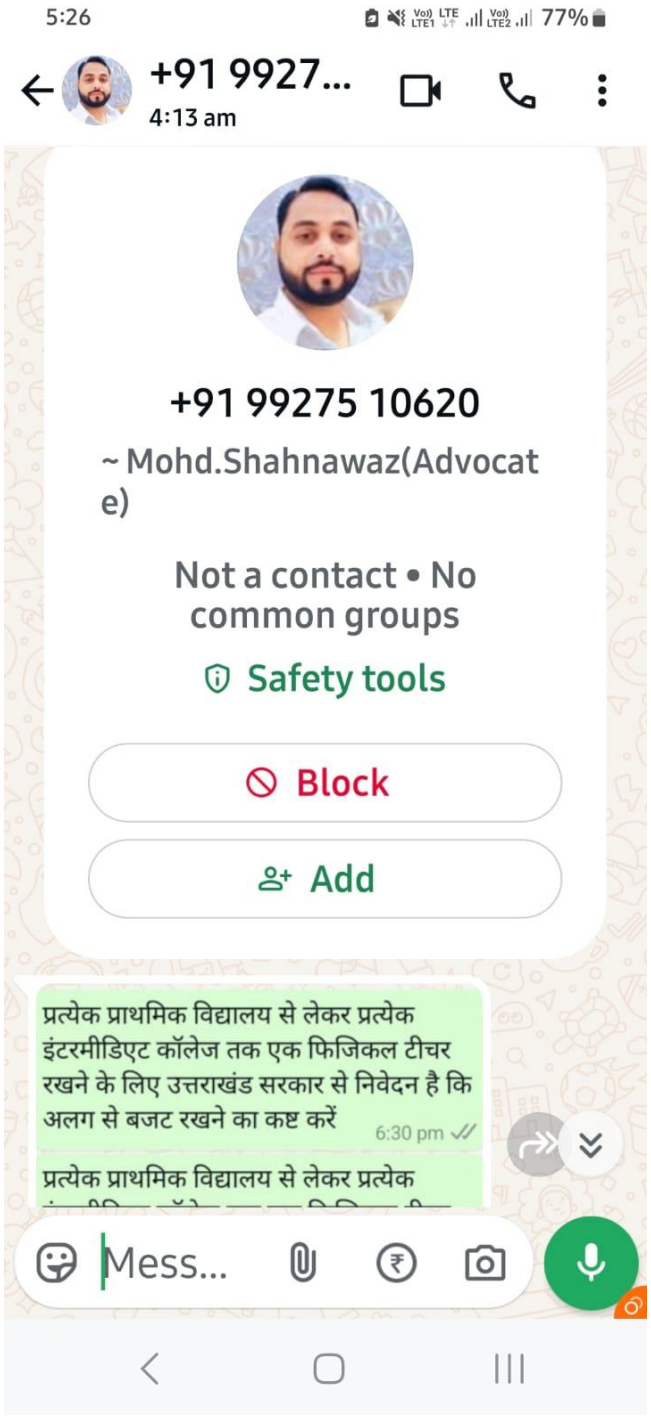
5:26
77%
+91 9927...
4:13 am
+91 99275 10620
~ Mohd.Shahnawaz(Advocate)
Not a contact • No common groups
Safety tools
Block
Add
प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय से लेकर प्रत्येक इंटरमीडिएट कॉलेज तक एक फिजिकल टीचर रखने के लिए उत्तराखंड सरकार से निवेदन है कि अलग से बजट रखने का कष्ट करें
6:30 pm
प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय से लेकर प्रत्येक
Mess...

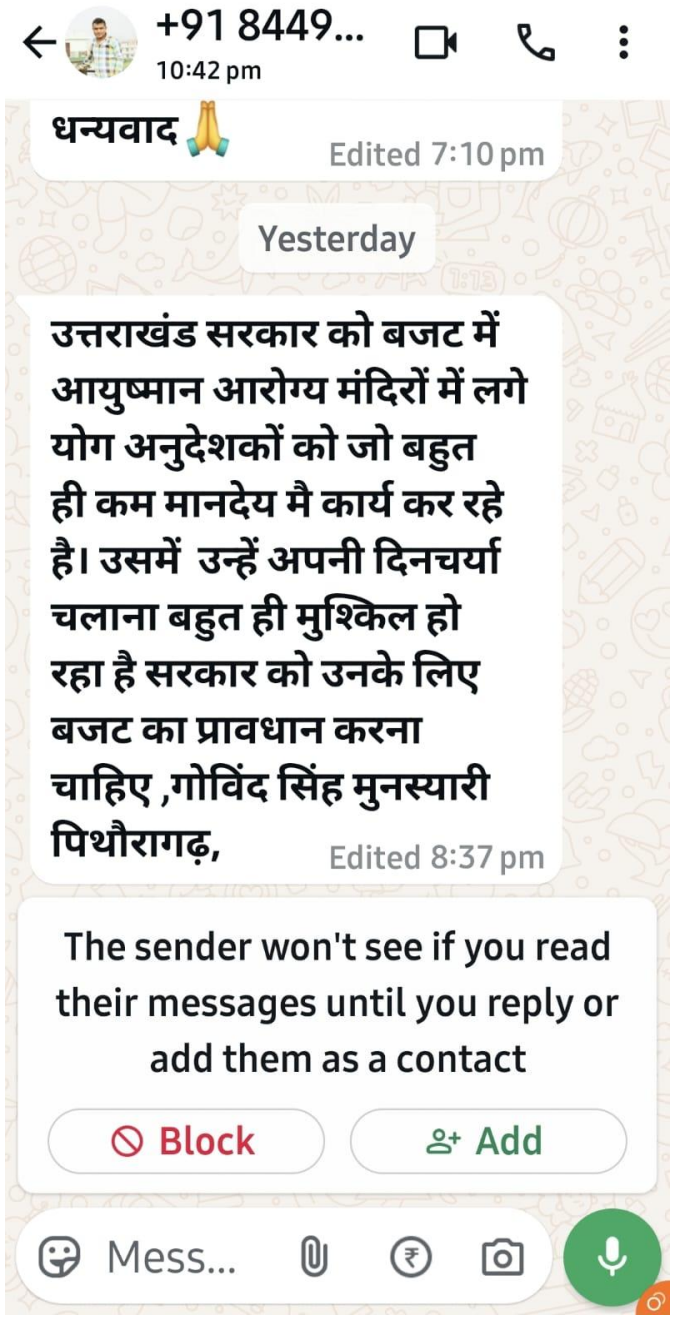
+91 8449...
10:42 pm
धन्यवाद 🙏
Edited 7:10 pm
Yesterday
उत्तराखंड सरकार को बजट में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में लगे योग अनुदेशकों को जो बहुत ही कम मानदेय मै कार्य कर रहे है। उसमें उन्हें अपनी दिनचर्या चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है सरकार को उनके लिए बजट का प्रावधान करना चाहिए ,गोविंद सिंह मुनस्यारी पिथौरागढ़,
Edited 8:37 pm
The sender won't see if you read their messages until you reply or add them as a contact
Block
Add
Mess...

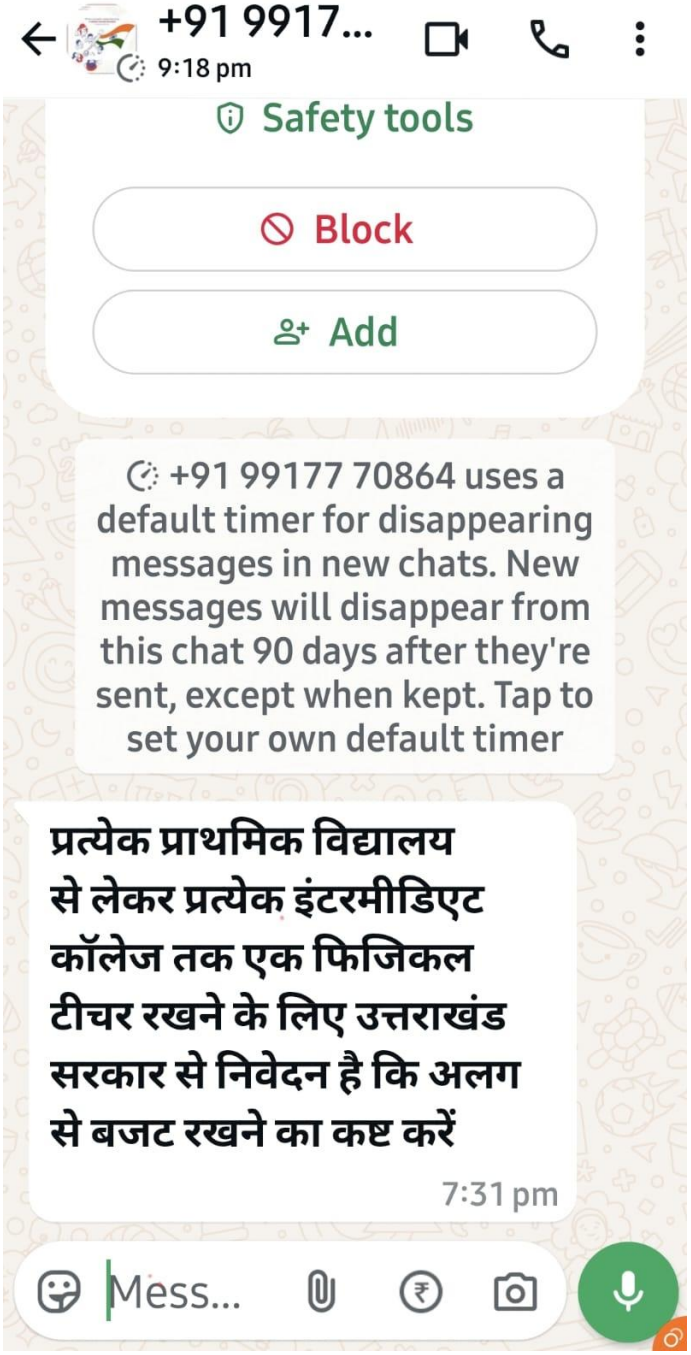
+91 9917...
9:18 pm
Safety tools
Block
Add
+91 99177 70864 uses a default timer for disappearing messages in new chats. New messages will disappear from this chat 90 days after they're sent, except when kept. Tap to set your own default timer
प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय से लेकर प्रत्येक इंटरमीडिएट कॉलेज तक एक फिजिकल टीचर रखने के लिए उत्तराखंड सरकार से निवेदन है कि अलग से बजट रखने का कष्ट करें
7:31 pm
Mess...

सेवा में,

श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी,
मा0 मुख्यमंत्री महोदय उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून।

विषय- **आगामी बजट निर्माण प्रक्रिया उत्तराखण्ड 2024-25 में जन आकांक्षाओं के अनुरूप जन कल्याणकारी सुझावों को सम्मिलित कराये जाने हेतु अति आवश्यक प्रार्थना।**

मा0 महोदय,

देवभूमि उत्तराखण्ड की सम्मानित आम जनता व कृषकों की आकांक्षाओं के अनुरूप प्रार्थी उत्तराखण्ड शासन की सेवा में निम्नलिखित महत्वपूर्ण एवं जन कल्याणकारी सुझावों को प्रेषित करते हुए यह अनुरोध करना चाहता है कि मा0 महोदय निम्न सुझावों को आगामी बजट 2024-25 के निर्माण प्रक्रिया में सम्मिलित कराये जाने की कृपा करेंगे।

सुझाव नम्बर (1)- देवभूमि उत्तराखण्ड के अन्तर्गत हमारी पूज्य आराध्या गौ माता (बद्री गाय/पहाड़ी नस्ल की गाय) का पिछले कुछ वर्षो से लगातार घोर अपमान होता आ रहा है जो कि निश्चित रूप से घोर विनाश के लक्षण हैं अतः देवभूमि के अन्तर्गत हर घर में बद्री गाय पालन योजना सुनिश्चित किये जाने की नितान्त आवश्यकता है जिस से एक तो उत्तराखण्ड राज्य के प्रत्येक घर में पवित्रता आयेगी तथा प्रत्येक घर में 33 करोड़ देवताओं का वास होगा। इसके साथ ही साथ यहाँ के कृषकों की भी आर्थिकी में बहुत वृद्धि सम्भव होगी।

सुझाव नम्बर (2)- देवभूमि उत्तराखण्ड के किसानों की आय को दोगुनी किये जाने के सम्बंध में काफी समय पूर्व से ही चर्चायें शासन द्वारा होती आ रही हैं परन्तु यह खेद का विषय है कि सरकार द्वारा कई योजनाऐं चलाये जाने के बावजूद भी धरातल पर संतोषजनक परिणाम नजर नही आ रहे हैं। अतः यहाँ के विशेष रूप से पर्वतीय किसानों के लिए अनुदान आधारित (पॉली हाऊस की तर्ज पर) जड़ी-बूटी के कृषिकरण हेतु एक विशेष योजना बनाये जाने की भी अत्यंत आवश्यकता है जिससे किसान अपनी निजी नाप भूमि में प्राकृतिक जीवन दायिनी जड़ी-बूटियों का उत्पादन कर अच्छा आर्थिक लाभ ले सकेंगे और इसके लिए शासन द्वारा किसानों के हित में उनके उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय बाजार दिलाये जाने की व्यवस्था किये जाने की भी नितान्त आवश्यकता है। परिणाम स्वरूप जहाँ एक ओर पर्वतीय किसानों की आय दोगुनी के बजाय कई गुनी बढ़ेगी वहीं देवभूमि उत्तराखण्ड की विश्व पटल पर एक विशेष पहचान होगी।

आशा है कि मा0 महोदय उपरोक्त जन कल्याणकारी एवं अत्यंत महत्वपूर्ण सुझावों को आगामी बजट निर्माण प्रक्रिया में सम्मिलित कराये जाने की कृपा करेंगे, और शासन द्वारा उपरोक्त विषय में की गयी कार्यवाही से प्रार्थी को भी अवश्य अवगत कराने की कृपा करेंगे। हम समस्त पर्वतीय जन व कृषक महोदय के आजीवन आभारी रहेंगे।

सधन्यवाद।

दिनांक: 03/01/2024

प्रार्थी

नारायण सिंह कुल्याल

नारायण सिंह कुल्याल
वरिष्ठ भा0ज0पा0 कार्यकर्ता, जंगलियागाँव,
वि0ख0- भीमताल, (नैनीताल) उत्तराखण्ड
मो0:- 8126669574

✎ *सर्व प्रथम उत्तराखंड में आयोजित हो रहे राष्ट्रीय खेलों के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ*

देश में सबसे पहले NEP 2020 लागू करने के लिए धन्यवाद

आप से विनम्र निवेदन है कि NEP 2020 के तहत कक्षा 1 से 12 वीं तक अनिवार्य शारीरिक शिक्षा व प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय से लेकर प्रत्येक इंटरमीडिएट कॉलेज तक शारीरिक शिक्षा कर रखना हेतु बजट आवांटित करने की कृपा कीजिएगा।

फिजिकल एजुकेशन यूनियन आपके जीवन भर आभारी रहेंगे

जगदीश चंद्र पांडेय

✎ *माननीय वित्त मंत्री जी,*

कृपया विचार करें निम्नमध्यवर्गीय परिवारों के विषय में -

5लाख आय वाले इस वर्ग के राशन कार्ड समाप्त कर दिए गए हैं जिससे स्वत ही आयुष्मान कार्ड की सेवा से वंचित कर दिया गया है।

नौकरशाही हावी हो रहीं हैं और इंस्पेक्टर राज के चलते और साथ ही ओनलाइन मार्किट के होते हुए लोकल व्यवसाय समाप्त होने को है।

इस वर्ग को कोई संरक्षण प्राप्त न होने से शोषण का शिकार हो रहे हैं जबकि सामाजिक सरोकारों को यही वर्ग बढ़-चढ़कर पूरा करता है। फिर चाहे नोटबंदी की आपदा हो या फिर कोराना काल की आपदा।

यदि इस वर्ग को कोई संरक्षण प्राप्त न हुआ तो व्यापार की सम्पूर्ण सप्लाई चेन ध्वस्त हो जाने से विराट संकट उत्पन्न हो जायेगा फिर चाहे जो भी उपाय करें इसकी भरपाई नहीं हो सकती हैं।

अतः इस वर्ग को विशेष प्रोत्साहन पैकेज दिया जाना आवश्यक है।

① Health/medicine →

ⓐ प्रदेश के सभी PHC, district hospitals व AIIMS आपस में एक common high speed communication media के द्वारा जुड़ जोड़े जायें। इसके लिए Telemedicine platform develop किया जाये। गाँव - 2 में पहुँच रखने वाली ASHA workers को भी इससे जोड़ा जाये, जिसके लिए उन्हें Free tablet उपलब्ध कराया जाये।

ⓑ Drone based drug delivery service start की जाये।

ⓒ प्रदेश के remote areas में medical store व Pathology lab खोलने के लिए subsidy दी जाये तथा इन्हें drone service से जोड़ने पर विचार किया जाये।

ⓓ Universities के लिए प्रारम्भ किये गये grading system की ही तरह District hospitals के लिए भी grading system शुरू किया जाये जिसका मूल्यांकन हर 4 या 6 माह में किया जाये।

② InFrastructure —

ⓐ Smart city की तरह smart district headquarters develop किये जायें। इसके लिए Smart city के सभी standard को follow किया जाये। इससे Villages में होने वाले migration को district level तक रोकने में help मिलेगी।

- बजट 2024-25के लिए मा.बित मनतरी जी दवारा जनता से मागा सुझाव सवागत योगय है.महोदय पहाडो मे बनजर पडी गाववालो की भूमी पर चाय बागान बिकसित किये जा सकते है उतराखणड टी बोरड से सरवे करवाने का बजट रखा जाय.निजि जमीन लीज रेनट पर ली जाय.इससे रोजगार के साथ साथ बयवसाय हो सकता है और पलायन भी रूक सकता है.आशा है पहाड के हित मे आप इस सूझाव को सवीकार करेगे. 2.पहाड के हर बिकास खणड लेबल पर परधान मनतरी कौशल बिकास परशिझण केनदर खोलने का बजट रखेगे.इससे गाव के छातर छातराये जो उचच शिझा के लिये कही नही जा पाते वे बिभिनन टरेडो मे अपने गाय ईलाके मे परशिझित होकर रोजगार सवरोजगार अपना सकते है.आभार.आवेदक बिधा दत पेटवाल उप परधान चौनड कोलगाव जाखकणीधार बलाक टिहरी.

✏ परम आदरणीय सादर नमस्कार, 🙏

मैं देहरादून का मूल निवासी हु व लगभग 36 वर्षो की बैंकिंग सेवा के पश्चात वर्ष 2020 में वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक के पद से सेवा निर्वत हुआ हु साथ एक सीमांत कृषक भी व खुद ही खेती करता हु इसके साथ साथ मैं वर्ष 1982 का मैरिट सूची वाला कृषि ग्रेजुएट भी हु इस नाते मैं आगामी बजट ,2024 के लिए अपने अनुभव के आधार पर कुछ सुझाव आपके संज्ञान के लिए प्रषित कर रहा हूं

1. चुकी हमारे प्रदेश में लघु व सीमांत किसानों की संख्या बहुत अधिक है लेकिन उनके विकास पर कुछ अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है जैसे इन वर्गों के लिए मिनी ट्रेक्टर,कृषि यंत्रों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए ब्लॉक स्तर पर अधिक से अधिक बजट आवंटन किया जाए देखने में आया है कि एक ब्लॉक में मात्र 2 या 3 ही ट्रेक्टर के लिए अनुदान का प्रावधान किया जा रहा हे जो इन कृषक वर्गों के लिए सही नही है साथ ही अनुदान के अंतर्गत ट्रेक्टर प्राप्त करने की जटिलताओं को भी कम किया जाए ।

2. कृषि हेतु नलकूप के लिए भूमि व अन्य मापडंडों को भी शिथिल किया जाए वर्तमान में जिन कृषिको के पास 12 बीघे से अधिक भूमि है वही नलकूप लगाने के लिए अनुदान के पात्र हैं

जबकि प्रदेश में 12बीघे से अधिक की जोत वाले बहुत ही कम कृषक है साथ ही ब्लॉक स्तर पर अनुदान के अंतर्गत लगने वाले नलकूप की संख्या में बड़ोतरी की जाए जो वर्तमान केवल2 या 3 ही है।

3. कृषि कार्य के लिए विद्युत बिल में अन्य राज्यों की भांति नॉमिनल चार्ज किया जाय या फ्री में कुछ यूनिट तक बिजली प्रदान की जाए जैसा की कई राज्य कर रहे है।

4.कृषि, सिंचाई व अन्य कृषि व सम्बन्धित कार्य के लिए अधिकतम छूट दी जाएताकि इन्हे सस्ते दामों में कृषक खरीद सके।

5. प्रदेश में बहुत जगह गुल या नहर के माध्यम से सिंचाई की सुविधा है लेकिन यह हमारे गरीब किसानो का दुर्भाग्य है कि उन्हें मानक स्तर का सिंचाई जल उपलब्ध नहीं हो रहा है बेतरतीब शहरी करण की वजह से अब किसानो को रसायन युक्त दूषित सिंचाई का जल उपलब्ध हो रहा है जिसे रोका जाना चाहिए खास तौर पर उन कृषि क्षेत्रों में जो शहर से सटे है।

6.विगत कुछ वर्षों से राज्य में बेसारा पशुओं की तादात बहुत ही अधिक हो है जिसके कारण उनके द्वारा कृष्को की फसल को नुकसान पहुंचा है इसके अतिरिक्त पहाड़ी क्षेत्रों में बंदरो द्वारा किसानों की फ़सल को बहुत ही नुकसान हो रहा है अतः शासन को इसकी रोकथाम हेतु कुछ आवशक कदम उठाए जाने चाहिए जैसे किसानो को तार बाड़ हेतु अनुदान दिया जाना चाहिए

साथ ही आवारा पशुओं के लिए अधिक से अधिक शेल्टर होम का प्रावधान बजट में घोषित किया जाए।

7. कृषि उपज को अच्छे दाम पर बेचने हेतु पंचायत स्तर पर रेगुलेटेड मार्केट की व्यस्था हेतु बजट में प्रावधान किया जाए ताकि किसानों को अपनी कृषि उद्पाद का यथोचित मूल्य मिल सके।

महोदय,आशा करता हु कि आप मेरे उपरोक्त बातों का संज्ञान लगे

भवदीय,

दिनेश चंद्रा गैरोला,

ग्राम मोथरोवाला,देहरादून।

9897523080

dinesh1960bankofindia@gmail.com

To
The Principal Secretary
Department of Finance
Government of Uttarakhand

Sub: Representation for Incentives to the Multiplex Industry in Uttarakhand – Budget 2025-26

Respected Sir/Madam,

In light of the upcoming budget exercise for 2025-26, we request the introduction of a robust incentive policy for the multiplex industry in Uttarakhand, aligning with the progressive measures undertaken by states like Uttar Pradesh. A well-structured incentive framework will not only enhance the viability of multiplex investments but also contribute significantly to employment generation, tourism promotion, and economic growth.

Key Recommendations:

1. **Entertainment Tax Reimbursement Mechanism:** Reinstate a reimbursement mechanism similar to the pre-GST era, ensuring a direct subsidy or adjustment through SGST for multiplex investments.
2. **Capital Investment Subsidy:** Provide capital subsidies for new multiplex projects and modernization/upgradation of existing ones, promoting infrastructure development.
3. **Interest Subvention on Loans:** Introduce interest subsidies on loans availed for multiplex construction to ease financial burdens.
4. **Impact of GST Implementation:** With the introduction of GST on 01.07.2017, the mechanism for adjusting the subsidy through entertainment tax collection became unviable. While the subsidy entitlement remains valid, the lack of a revised reimbursement mechanism post-GST has disrupted its implementation & recovery for the beneficiaries who are taking recourse to the legal channels.
5. **Land Allotment & Stamp Duty Exemptions:** Offer concessional land rates and stamp duty waivers to incentivize investments in underdeveloped and tourist-centric areas.
6. **Electricity & Infrastructure Support:** Provide subsidized electricity tariffs and infrastructure support, as multiplex operations incur high fixed costs.

A strong multiplex policy will position Uttarakhand as an investment-friendly destination in the film and entertainment sector, fostering tourism and economic prosperity. We request your kind consideration for including these provisions in the upcoming budget to stimulate much-needed private sector participation in the entertainment industry.

Yours sincerely,
Neeraj Sharda
Sharda Facility Management Pvt. Ltd.
Walkway Mall Multiplex, Haldwani
9837048050
Dated: 29.01.2025

सेवा में,

श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय

उत्तराखण्ड, सरकार।

महोदय,

हमें आज अपने राज्य उत्तराखण्ड और मुख्यमंत्री महोदय पर गर्व है कि आपने जनभावनाओं के सुझाव बजट हेतु मांगे है। हम राज्यवासी आपका और सरकार का दिल से सम्मान सहित धन्यवाद करते है।

मेरा यह सुझाव है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना 2005 में श्रमिक की वर्तमान में मजदुरी 237 रु0 प्रतिदिन है जो कि आज की दिनचर्या के खर्चो से बहुत कम है।

महोदय मेरा/हमारा सुझाव है कि इस मजदुरी दर को न्यूनतम 400 रु0 प्रतिदिन या अधिक किया जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों से हो रहा पलायन रूक सकें और हम ग्रामीण लोग मनरेगा में मजदुरी कार्य के साथ अपनी खेती बाड़ी (कृषि कार्य) भी कर सकें।

हमें अपने मुख्यमंत्री महोदय पर पूर्ण विश्वास है कि आगामी बजट वित्तीय वर्ष 2025–26 में इसकों रखने हेतु विचार विमर्श करेंगे, और इसको रखेंगे।

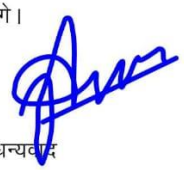

धन्यवाद

आनन्द सिंह पुत्र–श्री प्रताप सिंह

ग्राम पंचायत–अधौड़ा,ब्लॉक–भीमताल,

जिला–नैनीताल,पिन कोड–263001

फोन न0–8859566474,8057885151

सेवा में

श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी महोदय
उत्तराखण्ड सरकार

विषय – चंपावत जिले कोर्ट मे वकीलों के लिए चैंबर निर्माण हेतु

महोदय

सविनय इस प्रकार है कि जिला न्यायालय मे चैंबर ना होने से असुविधाओं का सामना करना पड़ता है तथा ना धामी जी निवेदन है कि चैंबर निर्माण हेतु राशि उपलब्ध कराने कि कृपा करे तथा युवा अधिवक्ताओं आर्थिक सहायता करने महीने को 5000 रुपया तक 3 वर्ष तक आर्थिक सहायता करने तथा लाइब्रेरी निर्माण तथा चैंबर निर्माण हेतु सहायता करे।

(1) चम्पावत जिले कोर्ट मे चैंबर निर्माण
(2) युवा अधिवक्ता को 5000 रुपया मासिक
(3) चम्पावत जिले कोर्ट मे लाइब्रेरी निर्माण

अत आपसे निवेदन है कि अर्धश चम्पावत कि जिला न्यायालय में मुलभूत सुविधा हेतु युवा वकिलों तथा चैंबर निर्माण हेतु मुख्यमंत्री जी अपनी घोषणा सामिल करने की कृपया करे

दिनांक | 26/011/2024

प्रार्थी
LOKMAN ADHIKARI (अध्यक्ष)
(signature)

सेवामे

श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय जी
पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखण्ड सरकार

महोदय

सविनय इस प्रकार है मैं गीता देवी ग्राम सभा पाड़ासीसेरा वि० बाराकोट जिला चम्पावत कि निवासी हूँ मेरा घर कच्चा मकान होने के कारण बारीश होने के कारण पुरा घर टपकता है इस घर मे रहने मे असमर्थ है तथा मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन कि ग्रामीण आवस योजना के तहत घर दिलाने कि कृप्या करे

अतः आपसे निवेदन है कि गीता देवी को जल्दी से जल्दी आवस बानाने के अतिसीघ्र घर बानाने के पैसा उपलब्ध काराने हेतु निवेदन है राज्य वित 2023-24 2023-24 के वित्त योजना पैसा उपलब्ध काराने हेतु परिवार की एक कामाने वाली महिला हुँ और मेरे पति की मृत्यु होने के कारण घर बनाने का सपना पुरा नही पाया अतः आपसे धामी जी आपसे आशा है कि हमारी सहायता करोगे आपकी रहुँगी

प्रार्थी
गीता देवी

दिनाक: 26/11/24

mobile No 9675916625
ग्राम पाड़ासीसेरा
वि० बाराकोट
जिला चम्पावत

सेवामें
श्रीमान मुख्य मंत्री जी महोदय
पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखण्ड सरकार

विषय बाराकोट तथा लोहाघाट निम्न समस्या

महोदय
सविनय इस प्रकार है कि मैं लोकमान अधिकारी कृष्णा बाराकोट तथा लोहाघाट की निम्न समस्या हेतु जिससे आदेश चम्पावत की ओर कार्य हो रहे तथा बहुत से समस्या है जो बाराकोट विकासखण्ड पिछड़ा है बाराकोट और लोहाघाट अति आवश्यता है विकास की

(1) बाराकोट एक ऐसा विकासखण्ड जहा महाविद्यालय नही है बाराकोट महाविद्यालय अति आवश्यता जिसमें नियम 15 से 20 हजार लोगो फायदा होगा
(2) बाराकोट की i.t.i. आई.टी.आई बन्द पड़ी खोलनी कृप्या करे
(3) बाराकोट खेल स्टेडियम का निर्माण करने कृप्या करे
(4) बाराकोट में SDM तथा तसीलदार की नियुक्ति करने कृप्या करे
(5) बाराकोट में तहसील मे कर्मचारीयो के सरकारी आवास बनाने हेतु
(6) बाराकोट मे नर्सिंग कॉलेज निर्माण कराने हेतु
(7) बाराकोट में सरकारी जॉब की तैयारी करने के लिए लाइब्रेरी का निर्माण
(8) बाराकोट विकासखंड मे सरकारी कर्मचारी के लिये आवास योजना
(9) बाराकोट प्राथमिक हॉस्पिटल का उचीकरण B block+IPE
(10) लोहाघाट हॉस्पिटल को बेस हॉस्पिटल उच्चीकरण करना
(11) लोहाघाट कृषि विज्ञान केन्द्र को कृषि महाविद्यालय घोषित करना
(12) लोहाघाट राजकीय पॉलिटेक्निक को इंजीनियरिंग कॉलेज दर्जा देना
(13) लडीधुरा मेला तथा श्यामधुरी मेले राजकीय घोषणा करना
(14) लोहाघाट मे होटल मैनेजमेंन्ट का कोलेज खोलने हेतु
(15) लोहाघाट में सैनिक स्कूल खोलने हेतु
(16) लोहाघाट मे आयुर्वेद महाविद्यालय खोलने हेतु
(17) लोहाघाट मे डी०ई०एल०एड महाविद्यालय खोलने हेतु
(18) लोहाघाट मे स्वामी विवेकानन्द हॉस्पिटल आधुनिक टैक्नोलॉजी निर्माण करना
(19) राईकोट गॉव झील निर्माण तथा पाडासेरा नदी मे डैम निर्माण
(20) पाटी विकासखंड के देवीधुरा के रमक गॉव मे झील निर्माण
(21) लोहाघाट व बाराकोट संस्कृत महाविद्यालय निर्माण
(22) लोहाघाट फिल्म सिटी निर्माण
(23) मल्लागॉव तथा बाराकोट हिमालय दर्शन निर्माण
(24) पीएचडी कोलेज निर्माण लोहाघाट में
(25) बीएफए बैचलर ऑफ फाइन आर्टस महाविद्यालय निर्माण लोहाघाट व बाराकोट मे

प्रार्थी
LOKMAN ADHIKARI (KRISHANA)
Mobile 967591662S

सेवामें

श्रीमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी
उत्तराखण्ड सरकार राज्य

विषय . ग्रामीण कि प्रमुख समस्या हेतु ग्राम सभा पाड़ासोसेरा

महोदय

सविनय इस प्रकार है कि ग्राम सभा की प्रमुख समस्या निम्न है तथा चम्पावत जिले के दुरस्थ गाँव होने के कारण यहा प्रमुख समस्या है तथा गाँव की निम्न समस्या हेतु मुख्य मंत्री जी से गाँव की समस्यो की हेतु

(1) पाडासोसेरा सड़क मे डामरीकरण करने हेतु
(2) पाडासोसेरा शिशि मार्ग बनावाने हेतु
(3) नौले का सौदयद्रयकरण करने हेतु
(4) शिव मंन्दिर सोन्दर्यकरण करने हेतु
(5) नदी मे पुल निर्माण हेतु तीन पुल निर्माण
(6) पाडांसोसेरा में ओपन जिम खोलने हेतु
(7) पाडासोसेरा मे गोशाला केन्द खोलने हेतु
(8) पाडासोसेरा मे शिशि मार्ग नौलधे से हाईस्कूल तक
(9) पाडासोसेरा में नौलधे से शिशि मार्ग कुण्डा तक
(10) पाडासोसेरा मे हाईस्कूल से ऊपर प्रथमिकस्कूल तक निर्माण
(11) पाडासोसेरा मे फल्पत्ति गधेरा निर्माण हेतु निर्माण
(12) पाडासोसेरा से सडक मिलान हेतु सिमलखेत तक सडक निर्माण
(13) पाडासोसेरा से सड़क से रैघाव सडक तक मिलान हेतु
(14) पाडासोसेरा से सिमली गॉव तक सडक निर्माण हेतु
(15) लोहाघाट बाराकोट सिमलखेत सडक निर्माण डबल लेन करने हेतु
(16) पाडासोसेरा मे ताडबाड योजना जंगलीजानवर बाचाने हेतु खेतीबाडी सुरक्षा बाड़ योजना
(17) पाडासोसेरा मे किसानो को टैकटर देने हेतु
(18) रैंगेधुरा मंन्दिर का सौदर्यकिरण तथा सड़क निर्माण डामरीकरण तथा धर्मशाला निर्माण तथा रैंचूला पुराना मंन्दिर सौदर्यकिरण तथा 400 मीटर शिशि निर्माण
(19) पाडासोसेरा मे जालो से विशाल घासे घास पहाडी कूड़ी घास लम्पा काटे घास जिसका रूप पुरे गॉव और जगंत तथा सड़क के किनारे जम चुके जिसका रूप बढ़ता जा रहा है सरकार को इनको रोकने कदम उठना चाहिये नही तो आने वाले दिनो मे आपनक ~~[illegible]~~ रूप ले लिगे सरकार जलदी से योजना बानानी चाहिये जिससे व खतम हो सके .
(21) पाडासोसेरा गॉव सोलर स्टीक लाइट 100 लाइट देने हेतु
(22) पाडासोसेरा मे सिचाई पंपिंग योजना मे खेती नाली निर्माण
(23)

प्रार्थी
LOKMAN ADHIKARI
KRISHNA
ग्राम पाडासोसेरा वि० बाराकोट जिला चम्पावत

(25) बारापका ...

✎ *आगामी बजट हेतु सुझाव/अनुरोध :-*

विभिन्न सरकारी परिसंपत्तियों में देखरेख के अभाव में टूट-फूट हो रही है जिस कारण उनका लाभ लंबे समय तक नहीं लिया जा सकेगा, जबकि उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस कर उनका अधिक समय तक सदुपयोग किया जा सकता है।

इससे सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा होने के साथ ही उनका अधिक समय तक सदुपयोग किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र से परिसंपत्तियां किराए पर नहीं लेनी पड़ेगी और विभागों में कार्य संपादन में भी सुगमता रहेगी।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत उत्तराखंड के पेयजल विभाग में भी नवीन कार्यालयों हेतु परिसंपत्तियों के सृजन, सृजित परिसंपत्तियों के सीमांकन, अनुरक्षण एवं रखरखाव हेतु आगामी राज्य बजट में समुचित धनराशि का प्रावधान किया जाने का सुझाव एवं अनुरोध है।

(इं0 अजय बैलवाल)
महासचिव,
पेयजल निगम डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ।

सर्व प्रथम उत्तराखंड में आयोजित हो रहे राष्ट्रीय खेलों के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ💐💐
देश में सबसे पहले NEP 2020 लागू करने के लिए धन्यवाद 🙏

आप से विनम्र निवेदन है कि NEP 2020 के तहत कक्षा 1 से 12 वीं तक अनिवार्य शारीरिक शिक्षा हेतु बजट आवांटित करने की कृपा कीजिएगा 🙏🙏

बीपीएड प्रशिक्षित बेरोजगारों को मिले नियुक्तिः धामी

खटीमा | हमारे संवाददाता

भाजपा विधायक पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हरीश रावत से बीपीएड प्रशिक्षित बेरोजगारों की नियुक्तियां को लेकर शीघ्र विज्ञप्ति जारी करने की मांग की है। धामी ने कहा है कि लम्बे समय से प्रदेश के बीपीएड प्रशिक्षित बेरोजगार नियुक्यिों की मांग को लेकर आंदोलित है। कई बार आश्वासन के बाद भी नियुक्तियों को लेकर विज्ञप्ति जारी नहीं हो पायी है। उन्होंने कहा है यदि शीघ्र नियुक्यिों नहीं दी जाती है तो भाजपा बीपीएड प्रशिक्षित बेरोजगारों के साथ मिलकर प्रदेश व्यापी आंदोलन करेगी। इधर, भाजपा कार्यालय पर आगामी चुनावों को लेकर भी एक बैठक की गयी। जिसमें भाजपा मंडल अध्यक्ष गोपाल बोरा ने बताया कि 11 फरवरी को जिला अध्यक्ष उत्तम दत्ता, जिला महामंत्री नन्दन सिंह खड़ायत तथा जिला प्रभारी मदन कौशिक खटीमा जी

मांग

- धामी ने सीएम हरीश रावत से विज्ञप्ति जारी करने की मांग की
- मांग न मानने पर प्रदेश सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी

जिला पंचायत सीटों के लिए संभावित प्रत्याशियों के नामों के आवेदन लेंगे। उन्होंने बताया कि इन्हीं आवेदनों के आधार पर भाजपा खटीमा के आठों सीटों पर जिला पंचायत प्रत्याशी का नाम घोषित करेगी।

बैठक में भाजपा कार्यकर्ताओं को पंचायत चुनावों में बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए तमाम जिम्मेदारी भी सौंपी गयी है। इस दौरान भाजयुमो जिला मंत्री अमित पाण्डेय, नवीन बोरा, जगदीश पंत, दीपक तिवारी, भुवन जोशी, रमेश

प्रधानमंत्री ने प्रशिक्षित बेरोजगारों ने मांगी नियुक्ति

देहरादून(नगर संवाददाता)। प्रदेश के बीपीएड एमपीएड प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश चंद पांडे ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार शारीरिक शिक्षा विषय व शारीरिक शिक्षक को उत्तराखंड के प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय से लेकर प्रत्येक इंटरमीडिएट कॉलेज तक अनिवार्य करने और नियुक्ति प्रदान किये जाने मांग की है।

उन्होंने पत्र में कहा है कि बीपीएड एमपीएड शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित बेरोजगार वर्ष 2006 से उत्तराखंड के सभी विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा विषय व शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति के लिए संघर्षरत है लेकिन राज्य सरकार के द्वारा इस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उन्होंने पत्र में कहा है कि कई बार प्रदेश के शिक्षा मंत्री डाक्टर धन सिंह रावत से मुलाकातर कर इस पर कार्यवाही करने के लिए बोला गया लेकिन केवल कोरे आश्वासन दिये जा रहे है और लोकसभा चुनाव बिल्कुल निकट है और इसलिए पत्र लिखा गया है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री को आदेशित कर इस समस्या का तुरत समाधान किया जाये।

उन्होंने पत्र में कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार शारीरिक शिक्षा विषय व शारीरिक शिक्षक प्रत्येक विद्यालय में अनिवार्य किया जाये और उच्च प्राथमिक विद्यालय में शारीरिक शिक्षा की नियुक्ति करने के संबंध में ई फाईल संख्या 27162 गतिमान है और इसके कैबिनेट में लाया जाये और व्यायाम का प्रवक्ता पद सर्जित किया जाये। इस अवसर पर पांडे ने बताया कि उल्लेखनीय है कि पूर्व में प्रशिक्षित बेरोजगार प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से मिलने उनके आवास यमुना कॉलोनी देहरादून मिलने पहुंचे और शिक्षा मंत्री से मिले और शिक्षा मंत्री डाक्टर धन सिंह रावत न कैबिनेट की बैठक में प्रशिक्षितों के मामले को रखने का आश्वासन दिया गया। इस अवसर पर जिसमें प्रशिक्षित बेरोजगार आज शिक्षा मंत्री डाक्टर धनसिंह रावत का घेराव व धरने पर बैठने के लिए आए थे और शिक्षा मंत्री डाक्टर धनसिंह रावत द्वारा बताया गया कि आज इस संबंध में शिक्षा सचिव से वार्ता की और कैबिनेट की बैठक में उच्च प्राथमिक विद्यालय में शारीरिक शिक्षक की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव कैबिनेट में लाने का शिक्षा मंत्री डाक्टर धन सिंह रावत द्वारा आश्वासन दिया जो कोरा साबित हुआ और इसके बाद कैबिनेट की बैठक भी हुई लेकिन उनके मामले को दरकिनार कर दिया गया जिससे प्रशिक्षित बेरोजगारों में रोष बना हुआ है।

देहरादून : उत्तराखंड में पिछले एक सप्ताह के भीतर एलटी एवं योग प्रशिक्षितों के लिए लगभग 1661 पदों पर शिक्षा विभाग में नियुक्तियां निकली है,वही दूसरी ओर बीपीएड एमपीएड शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित बेरोजगार वर्ष 2006 से विभाग में नियुक्ति के लिए प्रयासरत है एवं समय समय पर धरना प्रदर्शन और ज्ञापनों के जरिए शिक्षा मंत्री और सचिव से मुलाकात कर नौकरी की गुहार लगा रहे है।

इसी कड़ी में उत्तराखंड प्रदेश के बीपीएड एमपीएड प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश चंद्र पांडे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार शारीरिक शिक्षा विषय व शारीरिक शिक्षक को उत्तराखंड प्रदेश के प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय से लेकर प्रत्येक इंटरमीडिएट कॉलेज तक अनिवार्य करने और नियुक्ति प्रदान किए जाने की मांग की है।

उन्होंने पत्र में लिखा है कि बीपीएड एमपीएड शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित बेरोजगार वर्ष 2006 से उत्तराखंड के सभी विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा विषय व शारीरिक शिक्षा की नियुक्ति के लिए संघर्षरत हैं लेकिन राज्य सरकार के द्वारा इस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है उन्होंने पत्र में कहा है कई बार प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत से मुलाकात कर इस पर कार्रवाई करने का निवेदन किया गया लेकिन उनके द्वारा भी आजतक केवल कोरे आश्वासन दिए गए।

सामाजिक कर्ता –

70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों की बजट से अपेक्षा –

1- 50 वर्ग मी० में निवास कर रहे जनों को गृहकर से मुक्ति।

2- 50 यूनिट तक बिजली उपयोग पर बिल शून्य हो।

3- सार्वजनिक शौचालयों का उपयोग निःशुल्क हो।

4- सीवर कर समाप्त हो।

5- सरकारी चिकित्सालयों में पजी०/दवाई एक्सरे/अल्ट्रा साउण्ड निशुल्क हो।

6- सरकार, जनता के दरवाजे पर झूठी घोषणा न करे। क्योंकि 24 वर्ष की प्राइवेट नौकरी करने के बाद 2014 से EPFO पेंशन 948/- नौ सौ अड़तालीस रु० प्राप्त हो रही। वृद्धावस्था भी नहीं हो सकती क्योंकि आप यह पेंशन ले रहे

नमस्कार बजट में इस वित्तीय वर्ष के लिए राजधानी गैरसैंण के लिए बजट का प्रावधान अवश्य करें। गैरसैंण उत्तराखंड की राजधानी बनाई जानी चाहिए।नमस्कार बजट में इस वित्तीय वर्ष के लिए राजधानी गैरसैंण के लिए बजट का प्रावधान अवश्य करें। गैरसैंण उत्तराखंड की राजधानी बनाई जानी चाहिए।

shiv prasad sati

सर्व प्रथम उत्तराखंड में आयोजित हो रहे राष्ट्रीय खेलों के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ

देश में सबसे पहले NEP 2020 लागू करने के लिए धन्यवाद

आप से विनम्र निवेदन है कि NEP 2020 के तहत कक्षा 1 से 12 वीं तक अनिवार्य शारीरिक शिक्षा व प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय से लेकर प्रत्येक इंटरमीडिएट कॉलेज तक शारीरिक शिक्षा कर रखना हेतु बजट आवांटित करने की कृपा कीजिएगा।

फिजिकल एजुकेशन यूनियन आपके जीवन भर आभारी रहेंगे

जगदीश चंद्र पांडेय

सेवा में, अपर मुख्य सचिव,
वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

* * *

आपके द्वारा दैनिक जागरण, दिनाँक 24/12/2024 द्वारा "आपका बजट आपका सुझाव (बजट 2025-26)" के लिए माँगे गये सुझावों के लिए धन्यवाद करता हूँ और उपर्युक्त विषयक एक छोटा सा सुझाव निम्नवत् प्रेषित कर रहा हूँ जिससे उत्तराखण्ड यू० सी० सी० लागू करने वाले राज्य की भाँति पारदर्शी बजट पेश करने वाला प्रथम राज्य बन सके।

सुझाव :-

* * * प्रत्येक बजट राष्ट्र का हो या राज्य का उसमें एक दैनिक मजदूर से लेकर बड़े-बड़े उद्योगों एवं निर्माण कार्यों तथा सरकार द्वारा संचालित सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी विभागों पर होने वाले अनुमानित व्यय को तो दर्शाया जाता है लेकिन राज्य के किसी भी वेतनभोगी नेता को दी जाने वाली धनराशि, यथा- वेतन, पेंशन, आवासीय एवं चिकित्सा सुविधा, यात्रा-भत्ता एवं विधायक निधि इत्यादि को नहीं दर्शाया जाता, दर्शाने की कृपा करें ताकि आम जनता को ज्ञात हो सके कि हमारे खून-पसीने की कमाई हमारे हित में कार्य करने वाले नेता जो कि उसके वास्तविक हकदार हैं उन्हीं पर व्यय की जानी है।

दिनाँक : 01/02/2025 सुझावदाता — 1/2/2025

(तारादत्त पन्त)
2-205/1, टैगोर कालोनी,
पौलीशीट, काठगोदाम।
जिला-नैनीताल (यू०के०)

* * *

सेवा में

श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी महोदय
उत्तराखण्ड सरकार

विषय – चंपावत जिले कोर्ट मे वकीलों के लिए चैंबर निर्माण हेतु

महोदय

सविनय इस प्रकार है कि जिला न्यायालय मे चैंबर ना होने से असुविधाओं का सामना करना पड़ता है तथा ना धामी जी निवेदन है कि चैंबर निर्माण हेतु राशि उपलब्ध कराने कि कृपा करें तथा युवा अधिवक्ताओं आर्थिक सहायता करने महने को 5000 रुपया तक 3 वर्ष तक आर्थिक सहायता करने तथा लाइब्रेरी निर्माण तथा चैंबर निर्माण हेतु सहायता करे।

1. चम्पावत जिले कोर्ट मे चैंबर निर्माण
2. युवा अधिवक्ता को 5000 रुपया मासिक
3. चम्पावत जिले कोर्ट मे लाइब्रेरी निर्माण

अत आपसे निवेदन है कि अधिश चम्पावत कि जिला न्यायालय में मुलभूत सुविधा हेतु युवा वकिलो तथा चैंबर निर्माण हेतु मुख्यमंत्री जी अपनी घोषणा सामिल करने कि कृपया करे

दिनांक । 26/011/2024

प्रार्थी
LOKMAN ADHIKARI (हस्ताक्षर)
[signature]

महोदय सर्व प्रथम आप एवं सरकार के सभी गणमान्य मंत्रीगणों को बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं

बजट सत्र के लिए अपना सुझाव आपको भेज रहा हूं ।

उत्तराखंड सैनानियों को समान पेंशन का प्रावधान किया जाए।

उत्तराखंड में कार्यरत युवा कल्याण विभाग पी आर डी स्वयं सेवको को लगभग 30,000=00 रू मानदेय का प्राविधान बजट सत्र में किया जाय

पीआरडी जवानों को पूरे वर्ष भर सेवा में लिया जाय। पुनः निवेदन है कि उपरोक्त सुझाव को बजट में स्थान दें व पी आर डी स्वयं सेवक को स्थायी नियुक्त देने की कृपा करें।

उत्तराखंड जल संस्थान में लगभग 35 वर्षों से कार्यरत पी टी सी कर्मचारियों को नियमित करने का प्राविधान किया जाय।

आपका

आकांक्षी जगजीवन सिंह पंवार

उत्तराखंड राज्य सैनानी व आजीवन सदस्य भाजपा

पुरोला उत्तरकाशी

आदरणीय

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी

देहरादून,उत्तराखंड

सादर अभिवादन,

2025-26 के बजट निर्माण में जनता से मांगे गए सुझाव हेतु , आपका बहुत-बहुत आभार व धन्यवाद।

आपके मार्गदर्शन में विगत वर्षों की बजट निर्माण प्रक्रिया बहुत ही सराहनीय और बहुत ही प्रशंसनीय रही है, क्योंकि विगत सभी बजट संपूर्ण प्रदेश के लोगों के विकास तथा प्रकृति के सभी पहलुओं को समाहित करने वाले रहे है, इसी परिप्रेक्ष्य में 2025-26 बजट हेतु मेरे निम्न सुझाव प्रासंगिक हैं-

1) हमारे उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए,यहां की नैसर्गिक सुंदरता तथा प्रकृति को उसके स्वाभाविक स्वरूप व शाश्वतता को उसके पौराणिकता के अनुरूप अक्षुण्ण रखने हेतु प्रावधान...।

2) प्राकृतिक स्रोतों तथा विशेष रूप से वन क्षेत्र के दोहन से बढ़ते तापमान पर , अंकुश लगाने हेतु प्रावधान...

3) infrastructure हेतु जो बजट हो, वह इस प्रकार हो कि वह हमारी कृषि योग्य भूमि को उसर अथवा बंजर न बनाएं तथा हमारे जल के सभी स्रोतों की पवित्रता को कायम रख सके , आज हम जगह-जगह देखते हैं तो पाते हैं कि हमारी ज्यादातर नहरो के जल विषैले तथा काले रंग के हो गए हैं जो कि हमारी फसलों के सिंचाई के लिए भी उपयुक्त नहीं है।

4) आर्थिक विषमता के शिकार तथा निराश्रित लोगों के उन्नयन हेतु प्रावधान....
विशेष-माननीय मुख्यमंत्री जी आप ने राज्यवासियों के हितार्थ 'उत्तराखंड' को सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाने का जो संकल्प लिया है, आज वह हम सभी प्रदेशवासियों का संकल्प बन गया है, इसी संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान एक और विशेष विषय पर आकृष्ट करना चाहता हूं- राज्य में निवास करने वाली सभी युवा शक्ति , अपनी प्रतिभा ऊर्जा व सामर्थ्य का उपयोग सकारात्मक तथा उद्देश्य पूर्ण दिशा में कर सके, युवाओं में भटकाव की स्थिति न पैदा हो, इस महत्वपूर्ण कार्य हेतु grassroot level पर यदि योजना बनाई जा सके तो निश्चित ही हमारे प्रदेश के सभी युवा प्रदेश ही नहीं इस संपूर्ण देश को उन्नति के उच्च शिखर पर ले जाने में सहायक होंगे।

आपका

शुभेन्दु पाराशर पाण्डेय

ग्राम रामनगर (रुद्रपुर) जिला-उधम सिंह नगर

उत्तराखंड

फोन नंबर-9412969775

subhenduparashar@gmail.com